web: www.nyaysakshi.com ‖ पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल ‖ पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, रविवार 28 नवंबर 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-04, अंक- 61

महत्वपूर्ण एवं खास

ओडिशा में नदी में डूबे चार स्कूली छात्र, शव बरामद

भुवनेश्वर (आरएनएस)। ओडिशा के कटक में महानदी नदी में डूबे चार स्कूली छात्रों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान चंदन बेहरा, अजिंक्य बहलिया, शुभम सेठी और ओम प्रकाश बेहरा के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 13 से 14 वर्ष है। स्थानीय लोगों के अनुसार चारों गुरुवार दोपहर दो साइकिल से नदी में गए थे। शाम के समय लोगों ने देखा कि भादीमुल घाट के पास नदी के किनारे पर साइकिलें पड़ी देखी, जिसके बाद उन्होंने शोर मचा दिया। फिर उन लड़कों का पता लगाने के लिए एक तलाशी अभियान शुरू किया गया, जो सहपाठी थे। जहां एक शव बीती शाम बरामद किया गया, वहीं तीन अन्य के शव शुक्रवार को दमकल कर्मियों ने बरामद किए। चारों कटक शहर के चौलियागंज थाना क्षेत्र के नयाबाजार क्षेत्र के पोतापोखरी के रहने वाले थे।

किसानों का संसद ट्रैक्टर मार्च टाला, एमएसपी को लेकर किसान अपनी मांगो पर अड़िक

नई दिल्ली (आरएनएस)। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से कृषि कानून वापसी और किसानों की अन्य मांगों पर चिंतन करने के फैसले के बाद भी किसान संगठन अभी भी नरम नही हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान किया है कि 29 नवंर को संसद में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली नहीं की जाएगी लेकिन बगैर एमएसपी के हम पीछे नहीं हटेंगे। चार दिंसबर को फिर किसान बैठक करेंगे। शनिवार को दिल्ली में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा कि किसानों ने बैठक के बाद ये फैसला लिया है कि संयुक्त किसान मोर्चा 29 नवंबर को संसद में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली नहीं करेगा। हालांकि किसानों ने चेतावनी दी, कि बगैर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। इसके अलावा किसान शहीद हुए हैं, लखीमपुर खीरी मामले में किसान जेल भेजे जा रहे हैं। आज जो सरकार ने घोषणाएं की हम उससे सहमत नहीं है। सरकार हमारे साथ मंच साझा कर मामले पर वार्ता करे। लेकिन अगर 4 दिसंबर तक कोई फैसला नहीं हुआ तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से अपील की है कि वह घर लौट जाएं। तोमर ने कहा है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानूनों की वापसी के लिए विधेयक पेश करेगी। इसके अलावा एमएसपी पर किए वादे को भी पूरा किया जा रहा है तो पराली पर भी किसानों की बात मान ली गई है। ऐसे में प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं है।

चिदंबरम और उनके बेटे की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली की अदालत ने जारी किया समन

नई दिल्ली (आरएनएस)। एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कीर्ति चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने दोनों को समन जारी किया। इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल मैक्सिस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद शनिवार को राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और अन्य को समन जारी किया। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने इस मामले में सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने पहले अदालत को सूचित किया था कि एजेंसियों ने विभिन्न देशों को एलआर (लेटर रोगेटरी) भेजे थे और इस संबंध में कुछ घटनाक्रम हुए थे। सीबीआई ने यह भी कहा था कि वह एक नई लीड पर काम कर रही है। अदालत ने एजेंसियों से रिपोर्ट मांगते हुए कहा था कि पत्र में उल्लेखित आरोप काफी गंभीर प्रकृति के हैं। यह मामला जिसकी सीबीआई और ईडी द्वारा जांच की जा रही है, एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। FIPB की मंजूरी कथित तौर पर 2006 में दी गई थी जब चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।

'ओमिक्रोन' के मद्देनजर 'प्रोएक्टिव' रहने की जरूरत: मोदी

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस के नये स्वरूप 'ओमिक्रोन' का पता चलने और इसे लेकर दुनिया भर में पैदा हुई आशंकाओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 'प्रोएक्टिव' रहने की आवश्यकता जताई और संभावित खतरों के मद्देनजर अधिकारियों से अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की योजना की समीक्षा करने को भी कहा।

प्रधानमंत्री ने लोगों से अत्यधिक सतर्क रहने तथा मास्क पहनने व उचित दूरी सहित बचाव के सभी अन्य उपायों का पालन करने की भी अपील की। देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति और जारी टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने शीर्ष अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। लगभग दो घंटे चली इस बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को 'चिंता का विषय' बने 'ओमिक्रोन' और उसकी प्रकृति, विभिन्न देशों में इसके प्रभाव और भारत पर इसके असर के बारे में जानकारी दी और साथ ही संभावित प्रभावों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मोदी ने नए स्वरूप को देखते हुए 'प्रोएक्टिव' रहने की आवश्यकता के बारे में बताया।

पीएमओ के मुताबिक उन्होंने कहा कि नए खतरे को देखते हुए लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है और मास्क लगाने तथा सामाजिक दूरी का पालन करने जैसी उचित सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने 'जोखिम वाले' देशों के रूप में चिह्नित किए गए देशों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी अंतरराष्ट्रीय आगमन की निगरानी और दिशानिर्देशों के अनुरूप यात्रियों की जांच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने अधिकारियों से सामने आ रहे नये साक्ष्यों को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की योजना की समीक्षा करने को भी कहा। प्रधानमंत्री को देश में अनुक्रमण प्रयासों और फैल रहे कोरोना के स्वरूप का संक्षिप्त विवरण दिया गया। इस सिलसिले में उन्होंने निर्देश दिया कि जीनोम अनुक्रमण के नमूने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और समुदाय से नियमों के अनुसार एकत्र किए जाएं, उनकी आईएनएसएसीओजी (इंडियन सार्स-कोविड-2 कंसोर्टियम ऑन जिनोमिक्स) के तहत पहले से स्थापित प्रयोगशालाओं के नेटवर्क तथा कोविड-19 प्रबंधन के लिए चिह्नित शुरुआती चेतावनी संकेत के जरिए जांच की जाए।

प्रधानमंत्री ने अनुक्रमण प्रयासों को बढ़ाने और इसे और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता के बारे में बताया। बैठक के दौरान मोदी को टीकाकरण अभियान में प्रगति और हर घर दस्तक अभियान के तहत किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया गया। पीएमओ के मुताबिक मोदी ने दूसरी खुराक का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया और कहा कि जिन लोगों को पहली खुराक मिली है, उन्हें दूसरी खुराक समय पर दिया जाना राज्यों द्वारा सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री को समय-समय पर देश में होने वाले सीरो-पॉजिटिविटी और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया में इसके प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को राज्य और जिला स्तर पर उचित जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि ज्यादा कोविड मामलों वाली जगहों में गहन नियंत्रण और सक्रिय निगरानी जारी रहनी चाहिए और उन राज्यों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए जहां इस समय ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने वायरस के वेंटिलेशन और वायुजनित व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत पर भी बल दिया।

सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए बनाई 5 सदस्यीय समिति

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़े सभी काम समय पर पूरे हो सकें, इसकी निगरानी के लिए सरकार ने वित्त विभाग के पूर्व सचिव रतन पी. वाटल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को लेकर काम कर रही तमाम एजेंसियों के बीच बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित करने के लिए सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया है। यह समिति सेंट्रल विस्टा के लिए चल रहे विभिन्न कामों की प्रगति पर नजर बनाए रखेगी ताकि सभी काम समय पर पूरे हो सकें। इस निगरानी समिति को काम की गुणवत्ता पर भी नजर बनाए रखने का दायित्व दिया गया है।

मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, यह निगरानी समिति समय-समय पर काम की गुणवत्ता और प्रगति की स्वतंत्र समीक्षा के लिए साइट का दौरा करेगी, नियमित अंतराल पर बैठक करेगी और मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट और सुझाव देती रहेगी।

मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर को जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक डिप्टी कैग पीके तिवारी, एल एंड टी के पूर्व निदेशक शैलेन्द्र रॉय, आईआईटी दिल्ली की प्रोफेसर मौसम के अलावा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव को समिति में शामिल किया गया है।

सरकार द्वारा जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार इस सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी का गठन 2 वर्षों या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) के लिए किया गया है।

पराली जलाना अब अपराध नहीं, एमएसपी पर समिति बनेगी : कृषि मंत्री

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यह घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को की। उन्होंने कहा कि यह किसान संगठनों की बड़ी मांगों में से एक मांग थी कि पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए, इसलिए किसानों की यह मांग केंद्र सरकार ने मान ली है। दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दस दिसंबर 2015 को फसल अवशेषों पर जलाने का प्रतिबंध लगा दिया था। पराली जलाने पर कानूनी तौर पर कार्रवाई भी की जाती थी। पराली जलाते पकड़े जाने पर दो एकड़ भूमि तक 2,500 रुपये, दो से पांच एकड़ भूमि तक 5,000 रुपये और पांच एकड़ से ज्यादा भूमि पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता था।

इस दौरान कृषि मंत्री ने किसान संगठनों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है अब किसान आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। किसान बड़े मन का परिचय दें। प्रधानमंत्री की घोषणा का आदर करें और अपने-अपने घर लौटना सुनिश्चित करें। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की ओर से किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के गठन से किसानों की एमएसपी संबंधित मांग भी पूरी हो गई है।

कानून के प्रभाव का असर नहीं करतीं विधायिका : जस्टिस रमण

» बन जाते हैं बड़े मुद्दे, न्यायपालिका पर बढ़ रहा बोझ

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा है कि विधायिका (संसद व विधानसभाएं) उसके द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों के प्रभाव का अध्ययन या आकलन नहीं करतीं इस कारण ये कई बार बड़े मुद्दे बन जाते हैं। इस कारण न्यायपालिका पर भी मुकदमों का अत्यधिक बोझ बढ़ जाता है।

जजों व वकीलों को संबोधित करते हुए सीजेआई रमण ने कहा कि हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि हमें चाहे जिस आलोचना या बाधा का सामना करना पड़े, हमारा न्याय देने का मिशन नहीं रूक सकता। हमें न्यायपालिका को मजबूत करने व नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का हमारा मार्च जारी रखना है। जस्टिस रमण ने यह भी रेखांकित किया कि मौजूदा अदालतों का बगैर किसी खास बुनियादी ढांचे की स्थापना किए व्यावसायिक अदालतों के रूप में रिब्रांडिंग से लंबित मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में संविधान दिवस समारोहों के समापन कार्यक्रम को संबोधित

करते हुए सीजेआई ने कहा कि लंबित मुकदमों की समस्या बहुआयामी है। उम्मीद है कि सरकार इस दो दिनी समारोह में इस समस्या के समाधान के लिए आए सुझावों पर विचार करेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे।

सीजेआई रमण ने कहा कि दूसरा मुद्दा यह है कि विधायिका उसके द्वारा पारित किए जाने वाले कानूनों का अध्ययन या आकलन नहीं करतीं। इस कारण कई बार बड़े मुद्दे पैदा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में धारा 138 इसका एक उदाहरण है। इसके कारा पहले से केसों के बोझ में लदे मजिस्ट्रेटों पर ऐसे हजारों केस का बोझ और बढ़ गया है। इसी तरह विशेष बुनियादी ढांचे का निर्माण किए बगैर मौजूदा अदालतों की व्यावसायिक अदालतों के रूप में रिब्रांडिंग करने से लंबित मामलों का बोझ कम नहीं होगा।

लगातार सशक्त हो रहा भारत : राजनाथ सिंह

» प्रदेष में विकास का नया आयाम : आदित्यनाथ

जौनपुर (आरएनएस)। तिलकधारी महाविद्यालय के उमानाथ सिंह स्टेडियम में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार के द्वारा सभी पात्र लोगों को पक्का आवास दिया जा रहा है, घर-घर शौचालय बनवाया जा रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को लाभ दिया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की

प्रशंसा डब्ल्यूएचओ के द्वारा की गई है। भारत सरकार सम्पूर्ण भारत का विकास करने के साथ - साथ उ.प्र. का चहुमखी विकास कर रही है। विद्युत, उद्योग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है जिसकी संपूर्ण विश्व में सराहना होती है। उत्तर प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है, इज आफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर हुई है जिसके कारण देश विदेश के व्यापारी आकर्षित होकर निवेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार पहले की अपेक्षा बेहतर हुआ है, आधारभूत ढांचा के अंतर्गत यूपी में लगातार विकास कार्य किये जा रहे है। सड़क, पुल, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर के क्षेत्र में लगातार कार्य किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार मजबूत और सशक्त हो रहा है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा नित नए विकास के आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा कोरोना काल में मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई और एक भी व्यक्ति भूखा न रहे इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना योजना चालू की गई है जिसमें लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या द्वारा कहा गया कि केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के द्वारा प्रदेश की गरीब जनता को आवास, राशन, मुफ्त इलाज, की सुविधा दी जा रही है। पात्र लोगो को पक्का मकान, घर-घर शौचालय, उज्जवला योजना के तहत मुफ्त सिलेण्डर दिये जा रहे कैबिनेट मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडेय, राजेन्द्र प्रताप सिंह राज्यमंत्री आवास एवं शहरी नियोजन गिरीश चन्द्र यादव, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, सांसद मछलीशहर बी0पी0 सरोज सहित विधायकगण एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।

करमरी सरपंच के पति को नक्सलियों ने उतारा मौत के घाट

» जेसीबी को किया आग के हवाले, गांव में दहशत का माहौल

नारायणपुर (आरएनएस)। जिला मुख्यालय से करीब 21 किमी दूर ग्राम पंचायत करमरी में बीती रात नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों के द्वारा सरपंच के पति को मौत के घाट उतारने के बाद एक जेसीबी को आग के हवाले कर दिया है। एसपी गिरिजा शंकर जायसवाल ने घटना की पुष्टि करते कहा है कि इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पीएमजीएसवाई के कार्यपालन अभियंता विनय वर्मा ने बताया कि करमरी में पीएमजीएसवाई का निर्माण कार्य नहीं चल रहा है।

घटना को अंजाम देने के बाद नक्सलियों के द्वारा गांव में लाल बैनर लगाया गया है। नक्सली घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। शनिवार की सुबह मृतक के परिजनों के द्वारा फरसगांव थाना में एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है।

नेलनार एरिया कमेटी के द्वारा बिरजू की निर्मम हत्या करने के बाद गांव में बेनर लगाकर उसे जन विरोधी कहा गया है। नक्सली बेनर में पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर विकास कार्य करने वाले लोगों को मौत की सजा देने की बात कही गई है।

बारिश से दक्षिणी राज्यों में तबाह हुआ जन-जीवन, इस महीने 172 लोगों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। तमिलनाडु में हुई मूसलाधार बारिश ने कस्बों को बर्बाद कर दिया है, गांव के गांव तबाह हो गए और पांच लोगों की मौत हो गई। इसके बाद राज्य में मरने वालों की संख्या 68 हो गई। इसके अलावा अधिकारियों ने 2 दिसंबर तक दक्षिण भारत में और बारिश होने की चेतावनी भी दी है। 1 नवंबर से अब तक पांच दक्षिणी राज्यों में 172 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं, इसके बाद केरल में 48, आंध्र प्रदेश में 44 और कर्नाटक में 12 लोगों की मौत हुई है। हालांकि तेलंगावा में नवंबर में बारिश से संबंधित किसी भी मौत की सूचना नहीं है। तमिलनाडु में हालात इतने

खराब हैं कि लोगों को खाना स्टॉक करके रखना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी भर गया है जिससे जन-जीवन मुश्किल में पड़ गया है।

बारिश ने तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों जैसे तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई और नागपट्टिनम में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। थूथुकुडी में पिछले 24 घंटों में 250 मिमी की अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई। थूथूकुडी के एक निवासी ने कहा अत्तूर रोड पर पानी कूल्हे के लेवल तक है, जिसे अब बंद कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति से भी भारी बारिश की सूचना है। बेंगलुरु और दक्षिणी कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश हुई।

आईएमडी ने तमिलनाडु के पूरे तटीय क्षेत्र में 18 जिलों को रेड अलर्ट और तटीय क्षेत्रों से सटे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राज्य के 38 में से 37 जिलों में बारिश हुई और ज्यादातर जगहों पर स्कूल और कॉलेज बंद रहे।

राज्य के राजस्व और आपदा मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन ने कहा कि पांच लोगों की मौत अरियालुर, डिंडीगुल, शिवगंगा और तिरुवनम्माली से हुई है। उन्होंने कहा कि 10,503 लोगों को सरकारी राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।

राज्य भर में, लोगों ने भोजन का स्टॉक कर लिया, लेकिन रुके हुए पानी ने आम जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। चेन्नई के वेस्ट माम्बलम निवासी एस बालू ने कहा, हमने अभी-अभी अपना पूरा अपार्टमेंट साफ किया है और इसमें फिर से पानी भर गया है।

आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय और रायलसीमा जिलों में कई दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद शुक्रवार को स्थिति सामान्य हो गई। लेकिन कई क्षेत्रों से मध्यम बारिश की सूचना मिली थी और आईएमडी ने 2 दिसंबर तक इस क्षेत्र में और बारिश की भविष्यवाणी की थी।

मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य विधानसभा को बताया कि उनकी सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिना देर किए सभी राहत और बचाव के उपाय कर रही है और लोगों के लिए शिविर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 18 और 19 नवंबर को चार जिलों के 1,990 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे, जिनमें से 211 गांवों में पूरी तरह से पानी भर गयी था। कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई थी और 16 अभी भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि 1,169 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और 5,434 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए।

बेंगलुरु में पिछले 24 घंटों में ज्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र (केएसएनडीएमसी) ने कहा कि कोडागु, चिक्कमगलुरु, दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़, मैसूर और मांड्या जिलों में बारिश होगी। अधिकारी ने कहा, हालांकि, हमने आने वाले दिनों में राज्य में किसी भी भारी बारिश की भविष्यवाणी नहीं की है। हमारे मुताबिक, केवल छिटपुट, हल्की वर्षा होगी।